Body 75 residential units were to be provided per year to the Rajya Sabha and Lok Sabha Secretariats for ten years for allotment to their officers and staff and out of this only 305 residential units have been provided during the past ten years;

(b) if so, what are the reasons for the backlog of 445 residential units which were to be provided to these Secretariats as per the recommendation; and

(c) by when the remaining residential units are likely to be provided to these Secretariats?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir. Till date, 308 quarters in various categories have been placed at the disposal of Lok Sabha/Rajya Sabha Secretairats.

(b) and (c) Due to acute shortage of accommodation in general pool, it has not been possible to release 75 residential units annually.

गरीबों द्वारा दूध पीने के संबंध में भारतीय डेरी निगम की रिपोर्ट

2563. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय डेरी निगम द्वारा तैयार की गई उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि गरीब आदमी को प्रोटीन प्राप्ति के लिये दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह अमीर लोगों के लिए है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय डेरी निगम ने इसके क्या कारण बताए हैं;

(ग) उसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार गरीबों के लिए दूध मंहगा करने का विचार रखती है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय डेरी निगम की 1983–84 की वार्षिक रिपोर्ट देख ली है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि देश के करीब आठ राज्यों में राष्ट्रीय पोषक ब्यूरो, हैदराबाद द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि औसतन लगभग 19 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में प्रोटीन की खपत को मात्रा अपर्याप्त है, जबकि 39 प्रतिशत में कैलोरियों की खपत अपर्याप्त है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि प्रोटीन की कमी की अपेक्षा कैलोरी की कमी की समस्या अधिक व्यापक है; यह कि आमतौर पर उपलब्ध खाद्य सामग्रियों की पोषण क्षमता और उसकी कीमत के आधार पर तुलना करने से पता चलता है दूध (और पशुओं से प्राप्त लगभग सभी खाद्य सामग्रियां) कैलोरी की कमी को पूरा करने की दृष्टि से अधिक मंहगा विकल्प होगा यह कि प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये भी दूध एक मंहगा विकल्प है हालांकि यह मांस, मछली और अंडे की तुलना में सस्ता है, यह कि यद्यपि दूध के प्रोटीन को वनस्पति साधनों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन की तुलना में आमतौर पर बेहतर समझा जाता है, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी श्रेष्ठता इसकी अधिक कीमत के अनुपात में काफी कम है यह कि प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमियों को पूरा करने संबंधी विकल्पों पर विचार करते समय सिर्फ यह तर्कसंगत है कि निम्न आय वाला जनसमुदाय स्वयं को वनस्पति स्रोतों के सस्ते पोषक तत्वों से संतुष्ट कर लेते हैं और अमीर लोग पशु स्रोतों से मूलतः प्राप्त होने वाले पोषकों का उपयोग करते है यह कि इसके परिणाम स्वरुप दुग्ध उत्पादक, जो अपना फालतू दूध उन लोगों को बेचता है जो इसे खरीद सकते हैं और बिक्री से प्राप्त रकम का उपयोग प्रोटीन को 3–4 गुणा मात्रा और उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध में उपलब्ध कैलोरी की खरीद में कर सकता है। रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि गरीब आदमी को प्रोटीन प्राप्त करने के लिए दूध नहीं

मीना चाहिए अथवा दूध सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, अतः सरकार को राष्ट्रीय पोषक प्रबोधन ब्यूरो हैदराबाद द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर दिए गए निषकर्षों के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

Import of Phosphoric Acid

2564. SHRI K. MOHANAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India is one of the World's biggest buyers of phosphoric acid, whose demand may rise to 2.5 million tonnes by 1987-88;

(b) whether the present import of the phosphoric acid in liquid form is about 1.50 million tonnes;

(c) whether the said imports are being made on free on board basis;

(d) if so, what is the total quantity of this liquid imported on free on board during the last three years; and

(e) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) India is one of the major importers of phosphoric acid in the world. The anticipated demand by 1988 would be about 2.4 million tonnes of solution.

(b) The present imports of phosphoric acid in liquid form is about 1.4 million tonnes.

(c) and (d) Only smaller quantities have been imported, on occasions, on f.o.b. basis.

(e) Phosphoric acid is purchased on the basis of long term quantity contracts. Phosphoric acid requires special carriers. When these contracts were entered into no Indian shipping capacity capable of carrying Phosphoric acid was available. It was only in 1983 that one such Indian vessel became available. Recently, in the latter half of 1985 another vessel has been acquired. Both ships have been provided with adequate cargo. The policy of the Government is to give first preference to Indian carriers of Phosphoric acid. As part of this policy, whenever long-term contracts come up for renewal or new contracts are negotiated, f.o.b. basis., is to be adopted so far as Government| Government Controlled cargo is concerned In other cases also, quotations are invited on f.o.b. as well as c.i.f. basis to ensure maximum use of Indian carriers of Phosphoric acid.

खाद्य पदार्थों का संसाधन के दौरान बरबाद होना

2565. **श्री अश्विनी कुमार :**
श्री लालकृष्ण आडवाणी :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अक्तूबर, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि गत 5 अक्तूबर को चण्डीगढ़ में आयोजित तथा पंजाब के राज्यपाल द्वारा उद्घाटित मैकेनिकल इंजीनियर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बताया गया कि प्रोसेसिंग भंडारण और परिवहन के पुराने तरीकों के कारण लगभग 30 प्रतिशित संसाधित खाद्य पदार्थ बरबाद हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार सम्मेलन में की गई टिप्पणियों के संबध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

Contract signed with Independent Television Company

2566. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what are the terms, conditions, periods, and other details of the contract